

**भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3546
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

भारत-अमरीका संबंध

3546. श्री के. सुधाकरन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति से भेंट की है और यदि हां, तो उक्त बैठक के मुख्य परिणाम क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार ने भारतीय व्यापार, आब्रजन और रणनीतिक हितों पर "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (एमएजीए) नीतियों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारत ने एमएजीए के तहत संरक्षणवादी नीतियों के संबंध में चिंता व्यक्त की है जो अमरीका में भारतीय व्यवसायों और पेशेवरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अमरीकी प्रशासन की हाल की पहल के आलोक में भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए सरकार की कूटनीतिक रणनीति का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]**

(क) से (घ) प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर "आधिकारिक कार्य" यात्रा के लिए 12-13 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन डी.सी. का दौरा किया। नेताओं द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से सहयोग के प्रमुख स्तंभों में मूलभूत बदलाव लाने के लिए "21वीं सदी के लिए यू.एस.-भारत कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य व्यवस्था और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों का उत्प्रेरण)" का शुभारंभ किया गया।

दोनों नेताओं ने माल और सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने और बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहन बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य के लिए नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया - "मिशन 500" - जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है। नेताओं ने

पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की।

दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित करने के लिए अभिनव, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित आवाजाही ढांचों को लागू करना आवश्यक है। इस संबंध में, नेताओं ने छात्रों और पेशेवरों की वैध आवाजाही के अवसरों को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ अवैध आव्रजन और मानव तस्करी से भी कड़ाई से निपटने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत सरकार पारस्परिक चिंता के सभी मुद्दों पर रणनीतिक एकमतता को गहन बनाने के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव बनाए हुए है।
